

(b) whether further sums are to be allotted for the complete rehabilitation of the East Pakistani Refugees in the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI K.V. RAGHU. NATHA REDDY) : (a) Upto 31st March, 1973, an amount of Rs. 191.30 crores has been paid by way of compensation to Displaced Persons who held verified claims and as rehabilitation grant under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act and Rules framed there-under to those displaced persons who did not file claims or who came late from the former West Pakistan (now Pakistan).

Under the Nehru-Liaquat Pact of April, 1950, the migrants from East Pakistan retained proprietary rights in the properties left behind by them and they could sell, exchange or dispose of their properties in any manner they liked. Hence, no compensation was paid to them.

(b) Taking into account the magnitude of the problem, provision will be made in the Fifth Five Year Plan for the rehabilitation of migrants from the former East Pakistan.

बिहार की कोयला खानों में दुर्घटनाएं

308. श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन मास के दौरान बिहार राज्य के कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें कई मजदूरों की जानें चली गईं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इनमें गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की दुर्घटनाओं में जितने लोगों

की जानें गई उसकी तुलना में इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक लोगों की जानें गईं ; और

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार द्वारा मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

t[AcciDENis IN COALMINES IN BIHAR

308. SHRI V. K. SAKHLECHA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last three months serious accidents have taken place in the coal mines located in the coal fields of Bihar State, in which a number of workers lost their lives ;

(b) whether it is also a fact that serious accidents took place in the coal mines after their nationalisation and the number of people who lost their lives in these accidents was the highest as compared to the number of people who lost their lives in such accidents during the last three years ; and

(c) what steps have been taken by Government for the security of the workers after the nationalisation of coal mines ?]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० बॅकंटस्वामी) : (क) जीतपुर कोलियरी में 18 मार्च, 1973 को हुई दुर्घटना के अलावा, जिसमें 48 व्यक्ति मारे गये, तेरह और घातक दुर्घटनाएँ हुई जिनमें 14 श्रमिक मारे गये ।

(ख) जी नहीं, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जीतपुर कोलियरी की दुर्घटना का छोड़कर कोई और गंभीर दुर्घटना नहीं घटी ; बिहार कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की संख्या 1970 में 116, 1971 में 125 और 1972 में 90 थी ।

t[] English translation.

(ग) कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा विनियमों की प्रभावकारी क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI G. VENKAT SWAMY : (a) Apart from the Jitpur Colliery disaster which occurred on 18-3-73 involving the loss of 48 lives, there were 13 fatal accidents killing 14 workers.

(b) No, there has been no serious accident in coal mines after nationalisation excepting the Jitpur Colliery disaster ; the number of persons killed in accidents in Bihar coalfields was 116 in 1970, 125 in 1971 and 90 in 1972.

(c) Continuous efforts are being made by Directorate General of Mines Safety to ensure the effective implementation of safety regulations in coalfields.]

शरणार्थियों का पुनर्वास

309. श्री जोरेन्द्र कुमार सखलेचा :

श्री श्याम लाल गुप्त :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने छम्ब जोड़ियां अखनूर क्षेत्र (जम्मू और काश्मीर) से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है और इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और उक्त शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार को कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) उक्त शरणार्थियों में से कितने-कितने परिवारों को क्रमशः जम्मू और काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बसाया गया है और उनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) शेष शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

-(REHABILITATION OF REFUGEES

309. SHRI V. K. SAKHLECHA :

SHRI SHYAMLAL GUPTA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state ;

(a) whether the Government of Jammu and Kashmir has submitted any scheme to the Central Government with regard to the rehabilitation of the refugees from Chhamb-Jaurian-Akhnoor area (Jammu and Kashmir) and the amount of financial aid sought for this purpose and the amount which has been made available to the Government of Jammu and Kashmir to rehabilitate the said refugees ;

(b) the number of families out of the said refugees which have been rehabilitated by the Government of Jammu and Kashmir and the Government of India respectively and the money spent on their rehabilitation ; and

(c) the time by when the rehabilitation programme for the remaining refugees is likely to be completed ?]

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हाँ। जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार से प्राप्त हाल की सूचना के अनुसार 1,27,529 विस्थापित व्यक्तियों को पहले ही बसाया जा चुका है, 13,373 को अक्टूबर, 1973 तक बसा दिए जाने का प्रस्ताव है और 7,764 को अप्रैल, 1974 तक बसा दिया जाएगा। छम्ब के 18,422 विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास की योजना राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा तैयार की जानी है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1971 के भारत-पाक संघर्ष द्वारा प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों की निर्धारित दरों पर राशन और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था पर व्यय करने के अधिकार पहले ही दे दिए हैं। इस सम्पूर्ण व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

[] English translation.